

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 15 अगस्त, 2008

विषय:- गुरुनानक एजुकेशन ट्रस्ट को जनपद हरिद्वार के ग्राम खेडी शिकोहपुर ज0मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुडकी में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कुल रकवा 5.1140 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 788/भूमि व्यवस्था-भू0क0 दिनांक 25-06-08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 गुरुनानक एजुकेशन ट्रस्ट को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154(2) एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 25-06-08 के द्वारा संस्तुत खसरा नम्बरान के अनुसार जनपद हरिद्वार की तहसील रुडकी परगना भगवानपुर के ग्राम खेडी शिकोहपुर ज0मु0 में कुल रकवा 5.1140 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करतै हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक देनी तथा भूमि के विक्रय विलेख की पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर तकनीकी शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8- ट्रस्ट द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए किया जायेगा।

9- ट्रस्ट द्वारा कय की जाने वाली भूमि पर उतने ही तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे जितने एआईसीटीई के मानकानुसार अनुमन्य हैं।

10- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख की पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु नियमानुसार एआईसीटीई को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा दिनांक, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

11- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जायेगा।

12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

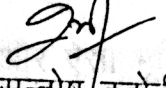
(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- श्री गुरसिमरन चड्ढा, मैनेजिंग ट्रस्टी, हाउस न0 31, नौर्थ एवेन्यू रोड, वेस्ट पंजाबी बांग नई दिल्ली- 110026 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 6- निदेश, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष/वडोनी)
अनुसचिव।